तूफान से मुस्तैद मुकाबला

जिस मेहनत और हौसले से ओड़िशा ने चक्रवात 'फोनी' का सामना किया है, उसकी पुरजोर सराहना आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है. बीस वर्ष पहले ऐसे ही तूफान से करीब 10 हजार मौतें हुई थीं. तब तबाही का आकलन 4.44 अरब डॉलर लगाया गया था, पर इस बार मौसम विभाग की सटीक सूचना और पूर्वानुमान तथा केंद्र व राज्य सरकारों की मुस्तैदी के कारण न सिर्फ बड़ी तादाद में लोगों को बचाया जा सका, बल्कि संपत्ति को बचाने में भी बहुत हद तक कामयाबी मिली है. अब तक मरनेवालों की संख्या 16 बतायी जा रही है. जेनेवा में 13 मई से होनेवाली आपदा प्रबंधन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इस प्रकरण पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव है. तूफान से निबटने की ठोस तैयारी का ही नतीजा है कि इसके गुजरने के साथ ही इससे प्रभावित 10 हजार गांवों और 52 शहरी इलाकों में राहत और पुनर्वास का काम शुरू कर दिया गया है. ओड़िशा की यह उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है. हमारा देश दुनिया के उन हिस्सों में से है, जहां प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला बना रहता है. ऐसे में ओड़िशा के अनुभव पूरे देश के लिए आदर्श होने चाहिए. सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, सामुद्रिक विज्ञान, मौसम, सूचना आदि के क्षेत्र में हमारे पास विकसित अत्याधुनिक तकनीक हैं, जिनके सहारे आपदाओं का अनुमान लगाना आसान हुआ है. इन अनुमानों के आधार पर समुचित संसाधन और सक्षम प्रबंधन के सहारे जान-माल को बचाया जा सकता है. सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस लगन और मेहनत से राज्य पुलिस और प्रशासनिक महकमे ने 12 लाख लोगों को 24 से 36 घंटे में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सही ही इसे इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है. उल्लेखनीय है कि 1999 के तूफान के समय मुख्यमंत्री आवास में एक सैटेलाइट फोन हुआ करता था और खराब मौसम के कारण सामान्य टेलीफोन सेवा बाधित थी, लेकिन इस बार लाखों मोबाइल संदेश भेजे गये, मछुआरों को वायरलेस से आगाह किया गया तथा लाउडस्पीकरों के साथ रेडियो व टेलीविजन से लगातार सूचनाएं दी गयीं. तूफान जाते ही दूरसंचार और यातायात सेवाओं को एक हद तक बहाल भी कर लिया गया. तकनीकी विकास, मानवीय सक्रियता और साजो-सामान के इंतजाम ने इस आपदा की चुनौती का कामयाब मुकाबला किया है. ओड़िशा ने 1999 की तबाही से सबक लिया और आज नतीजा सामने है. अब पूरे देश को ओड़िशा से सीखने की जरूरत है. मुंबई, चेन्नई और केरल की बाढ़ की विभीषिका को बहुत दिन नहीं हुए हैं. ये इलाके हर मायने में ओड़िशा से विकसित हैं, पर वे बर्बादी को कमतर नहीं कर सके. केंद्रीय और राज्यस्तरीय आपदा प्रबंधन के विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों को चुस्त-दुरुस्त बनाने के साथ इनके अन्य विभागों से बेहतर तालमेल पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. सूचना, संसाधन, प्रबंधन और प्रशासन की सहभागिता से ओड़िशा की तरह आपदाओं का मुकाबला संभव है.

तकनीकी विकास, मानवीय सक्रियता और साजो-सामान के इंतजाम ने इस आपदा की चुनौती का कामयाब मुकाबला किया है.

फेक न्यूज के दौर में विश्वसनीय हैं अखबार

आशुतोष चतुर्वेदी
प्रधान संपादक, प्रभात खबर
ashutosh.chaturvedi
@prabhatkhabar.in

अखबार अपनी छपी खबर से पीछे नहीं हट सकता है. अखबार की खबरें काफी जांच पड़ताल के बाद प्रकाशित की जाती हैं. लिहाजा, प्रभात खबर ही नहीं अन्य अनेक अखबारों के पाठकों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार है. यह भेद कर पाना बेहद कठिन है कि कौन-सी खबर सच है, कौन-सी खबर फर्जी है. व्हाट्सएप के दौर में सुबह से शाम तक खबरों का आदान प्रदान होता है और पता ही नहीं चलता कि कितनी तेजी से फेक न्यूज के आप शिकार हो गये और आपने उसे आगे बढ़ा कर कितने और लोगों को प्रभावित कर दिया. एक और मुश्किल है कि इसके स्रोत का पता ही नहीं चलता है. यह फॉरवर्ड होती हुई आप तक पहुंचती है. फेक न्यूज की समस्या इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. चुनावी मौसम में तो इनकी बाढ़ आ गयी है. अभी भारत की 27 फीसदी आबादी यानी लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग भारत में हैं.

हाल में ऐसी कई खबरें आयीं हैं, जब लोगों को गुमराह करने वाली खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गयीं. हाल में फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सएप पर हेमामालिनी की दो तस्वीरें वायरल हुई थीं. एक में वह हेलीकॉप्टर से उतरती हुई दिख रही हैं और दूसरी में खेत में गेहूं की फसल काट रही हैं. दोनों तस्वीरों के साथ वायरल था कि 'मोदी जी पर गर्व है. महिला किसानों को हेलीकॉप्टर दिये जा रहे हैं, जिससे वे खेत तक पहुंच रही हैं.' पड़ताल में पाया गया कि ये दोनों तस्वीरें इस साल की नहीं हैं. हेलीकॉप्टर वाली तस्वीर 2015 की है और दूसरी तस्वीर 2014 की. दोनों तस्वीरों को मिला कर फेक तस्वीर तैयार की गयी.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कांग्रेस और राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति वाराणसी संसदीय क्षेत्र से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय हैं, जबकि यह सही नहीं है. पड़ताल में पता चला कि यह वीडियो भोपाल के कारोबारी अनिल बूलचंदानी का है.

कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक और खबर जोर-शोर से चली थी कि अगर कोई वोट नहीं डालेगा, तो उसके बैंक अकाउंट से 350 रुपये कट जायेंगे. प्रमाण के रूप में अखबार की एक फेक न्यूज नत्थी कर दी गयी थी. इस फेक न्यूज ने अनेक लोगों को विचलित कर दिया. बाद में स्पष्टीकरण आया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक और पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि पहली जून से सभी बैंक हर शनिवार को बंद रहेंगे. दावा किया जा रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को सिर्फ पांच दिन काम करने की मंजूरी दे दी है. बैंकों के कामकाज का समय सोमवार से शुक्रवार तक समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा. इस फेक न्यूज को एक न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज के रूप में पेश किया गया था. बाद में आरबीआइ को इसका खंडन करना पड़ा.

ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें फेक न्यूज को तथ्यों के आवरण के साथ लपेट कर पेश किया गया, ताकि आम व्यक्ति उस पर भरोसा कर ले. इनके अलावा ऐसी भी खबरें फैलायी जाती रही हैं, जिनसे जातिगत और धार्मिक वैमनस्यता फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है. ऐसी कई घटनाएं हैं, जिनमें सोशल मीडिया की खबर ने इलाके में तनाव फैला दिया है. दरअसल, भारत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है. विभिन्न स्रोतों से मिले आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में व्हाट्सएप के एक अरब से अधिक सक्रिय यूजर्स हैं. इनमें से 16 करोड़ भारत में ही हैं. फेसबुक इस्तेमाल करने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 15 करोड़ है और ट्विटर अकाउंट्स की संख्या 2 करोड़ से ऊपर है. लगभग 40 करोड़ भारतीय आज इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं. हमें करना यह चाहिए कि कोई भी सनसनीखेज खबर की एक बार जांच अवश्य करें. मैं जानता हूं कि यह करना आसान नहीं है. इससे कैसे निबटा जाए, यह अपने आप में बड़ी चुनौती है.

दूसरी ओर अखबारों की ओर नजर दौड़ाएं. आज भी ये सूचनाओं के सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं. अखबार अपनी छपी खबर से पीछे नहीं हट सकता है. अखबार की खबरें काफी जांच पड़ताल के बाद प्रकाशित की जाती हैं. अखबारों के खिलाफ एकतरफा फैसला सुनाने वाले आपको बहुत-से लोग मिल जायेंगे, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि पत्रकार कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम देते हैं. कुछ समय पहले श्रीनगर में राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की आतंकवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी. त्रिपुरा में पिछले साल दो पत्रकारों की हत्या कर दी गयी थी. बेंगलुरु में गोरी लंकेश की हत्या तो चर्चित रही ही है. मप्र के भिंड इलाके में रेत माफिया और पुलिस का गठजोड़ उजागर करने पर एक पत्रकार को ट्रक से कुचल कर मार दिया गया था. यह कोई दबा-छुपा तथ्य नहीं है कि मीडियाकर्मियों को कई तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है. इसमें राजनीतिक और सामाजिक, दोनों दबाव शामिल हैं. इतने दबावों के बीच आप अंदाज लगा सकते हैं कि खबरों में संतुलन बनाये रखना कितना कठिन कार्य होता है. प्रभात खबर की बात करें, तो हमने सबसे अधिक घपले-घोटाले उजागर किये हैं, जिसके कारण कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों तक को जेल तक जाना पड़ा है. यही वजह है कि हाल में मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल द्वारा आयोजित इंडियन रीडरशिप सर्वे, 2019 की पहली तिमाही का परिणाम आया है, जिसमें टोटल रीडरशिप में प्रभात खबर 1 करोड़ 41 लाख पाठकों के साथ हिंदी अखबारों में देश का 5वां सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार बन गया है. सभी भाषाओं के अखबारों में प्रभात खबर 10वें स्थान पर है. झारखंड में करीब 48 लाख पाठकों के साथ प्रभात खबर अन्य अखबारों की तुलना में राज्य का सबसे बड़ा अखबार बना हुआ है. ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की जुलाई-दिसंबर, 2018 की रिपोर्ट के आधार पर भी प्रभात खबर झारखंड का नंबर वन अखबार है. बिहार में प्रभात खबर 88 लाख 20 हजार पाठकों के साथ राज्य का दूसरा सबसे पढ़ा जाने वाला अखबार है. पिछले सर्वेक्षण की तुलना में वर्ष 2019 की पहली तिमाही के सर्वेक्षण के आधार पर बिहार में 6 लाख 10 हजार नये पाठक जुड़े हैं. एवरेज इश्यू रीडरशिप, 2019 की पहली तिमाही के अनुसार पश्चिम बंगाल के हिंदी अखबारों में प्रभात खबर 1 लाख 65 हजार पाठकों के साथ दूसरे स्थान पर है. प्रभात खबर ही नहीं अन्य अनेक अखबारों के पाठकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. यह दिखाता है कि अखबार आज भी खबरों के सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं.

बोधि वृक्ष

मानवीय परत

मानवीय विकास का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना हो, तो यह मान कर नहीं चला जा सकता कि मनुष्य शरीर पाने तक ही उसकी अंतिम परिधि है. उसे विकासोन्मुख होने के लिए शरीरगत जीवनयापन को भी सब कुछ न मान कर अपनी सत्ता चेतना के साथ जोड़नी पड़ेगी, जो इस ब्रह्मांड पर अनुशासन करती और अंतराल को सुविकसित, स्वच्छ बना लेनेवालों पर अपनी उच्च स्तरीय अनुकंपा बरसाती है. साथ ही, मनुष्य को इस प्रकार का चिंतन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि उसके अंतराल में अति महत्वपूर्ण क्षमताओं का भी भंडार भरा पड़ा है, जिन्हें थोड़ा विकसित कर लेने पर वह काया की दृष्टि से यथावत रहते हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से महानतम बन सकता है. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है. वह प्रकृति की कठपुतली मात्र नहीं. अन्य प्राणियों की तरह मात्र निर्वाह ही उसकी एकमात्र आवश्यकता नहीं है, वरन व्यक्तित्व का स्तर उठाकर जीवन सज्जा को अनेक उपलब्धियों-विभूतियों से अलंकृत करना भी एक विशिष्ट उद्देश्य है. जब तक यह विचारणा नहीं उठती, तब तक वस्तुतः मनुष्य नर-पशु ही रहता है, इंद्रिय लिप्साओं व मानसिक तृष्णाओं तक ही उसकी गतिविधियां सीमित रहती हैं, न वह जीवन का महत्व समझ पाता है, और न उसे चेतना की पृथकता, विशिष्टता संबंधी कुछ ज्ञान होता है. इस अध्यात्म विकास के तत्वज्ञान के अनुरूप चेतना को विकसित, परिष्कृत, समर्थ, विलक्षण बनाने का द्वार मनुष्य शरीर मिलने के उपरांत खुलता है. इससे पूर्व तो वह मात्र जीवधारी ही बनकर रहता है. साथ ही, प्रकृति का अनुशासन मानने के लिए बाधित रहता है. उसे प्रकृति पर अनुशासन करने, उसे अपने अनुकूल बनाने की विद्या का ज्ञान तक नहीं होता. विकास की मानवीय परत में उभरते ही उसे आत्मबोध की एक नयी उपलब्धि हस्तगत होती है, वह अनुभव करता है कि काय-कलेवर उसका समग्र स्वरूप नहीं, वरन एक वाहन उपकरण आच्छादन मात्र है.

पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य

चुनाव के असली मुद्दे

रविभूषण
वरिष्ठ साहित्यकार
ravibhushan1408@gmail.com

सत्तर वर्ष के आजाद भारत में पीने का पानी, अच्छे कपड़े, भोजन, घर, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और निर्भीक वातावरण क्यों नहीं हैं? ये सब चुनाव के जरूरी मुद्दे हैं. चुनाव का जरूरी मुद्दा आतंकवाद और राष्ट्रवाद नहीं है.

चुनाव को 'लोकतंत्र का महापर्व' कहा जाता है और विगत कई वर्षों से भारतीय लोकतंत्र लगातार बहस और विमर्श में है. स्टीन लेविट्स्की और डैनिअल जिवलैट ने अपनी पुस्तक 'हाउ डेमोक्रेसीज डाइ : व्हॉट हिस्ट्री रिवील्स अबाउट आवर फ्यूचर' (2018) में उदाहरण सहित बड़े विस्तार से यह बताया है कि किस प्रकार लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गयी सरकारें भी लोकतंत्र को समाप्त करती हैं. यह तभी संभव हो पाता है, जब हमारी लोकतांत्रिक-संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जाता हो, उनकी स्वायत्तता समाप्त की जाती हो और वे अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर रही हों. लोकतंत्र में सैद्धांतिक बातें की जाती हैं. हवा-हवाई बातें कुछ क्षणों के लिए हमें रोमांचित-आह्लादित करती हैं, पर महत्व उन जमीनी सच्चाइयों का है, जिनका हमें एक साथ पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सामना करना पड़ता है.

चुनाव में कब किन स्थितियों में सामाजिक-आर्थिक मुद्दे गौण होते हैं और धार्मिक मुद्दे प्रमुख? राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों का ऐतिहासिक और समकालीन अध्ययन समाज विज्ञान में भी कम होता है. किसी भी दल विशेष का चुनावी मुद्दा किन अर्थों में दूसरे दलों के चुनावी मुद्दों से भिन्न होता है? क्या मतदाताओं को चुनाव के समय और चुनाव के बाद अपने नेताओं और उनके राजनीतिक दलों से सवाल नहीं पूछना चाहिए? अक्सर नेता वादे करके मुकर जाते हैं, आश्वासन देकर उसे पूरा नहीं कर पाते, जो उनके लिए जितना भी लाभदायक क्यों न हो, जनता और लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है. सामान्य मतदाताओं और उनके परिवार का जीवन जिन मुश्किलों और समस्याओं के बीच गुजरता है, उसके समाधान और निराकरण की पूरी जिम्मेदारी सत्ताधारी राजनीतिक दल की है. चुनाव के असली मुद्दों और नकली मुद्दों में अंतर है. असली मुद्दे हमारे दैनिक जीवन से, हमारी सामान्य आवश्यकताओं से जुड़े हैं. ये जरूरी मुद्दे हैं, जिनमें शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, रोजगार की गारंटी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बुनियादी आवश्यकताएं हैं. भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा नहीं बन सकता. कोई भी मतदाता मतदान क्यों करता है? वह अपने जीवन की बेहतरी के लिए मतदान करता है या बदतरी के लिए? प्रदेश की राजधानी में जब जल-संकट हो, पेयजल की कोई सुविधा नहीं हो, तो इसके लिए सरकार, सत्ता-व्यवस्था दोषी है या मतदाता भी? मतदाताओं की पहली चिंता अपने जीवन को बेहतर बनाने की होती है. वह यह नहीं समझ पाता कि चुनाव के समय ही वह दाता 'भाग्य विधाता' और 'ईश्वर' की भूमिका में कैसे आ जाता है? मतदान करते समय बटन दबाना अपने भविष्य को किसी को सौंप देना है, नेता-विशेष और दल-विशेष पर विश्वास कायम करना है, पर बार-बार वह ठगा जाता है, उससे वादा-खिलाफी की जाती है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि वह सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री किसी से सवाल तक नहीं पूछ सकता.

आतंकवाद और राष्ट्रवाद एक मुद्दा है, पर संप्रति यह देश का प्रमुख मुद्दा नहीं है. राष्ट्रवाद को किसी दल-विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता. जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कुछ गैर जरूरी मुद्दे सामने लाये जाते हैं. वोट को लेकर अक्सर कई नारे लगाये जाते हैं- 'लोकतंत्र का यह अधिकार/ वोट न कोई हो बेकार', 'लोकतंत्र की सुनो पुकार/ मत खोना अपना अधिकार', 'बहकावे में कभी न आना/ सोच-समझ कर बटन दबाना', 'न नशे से न नोट से/ किस्मत बदलेगी वोट से' आदि. मतदाताओं के समक्ष सदैव यह मुश्किल रही है कि वह अपना वोट प्रत्याशी-विशेष या दल-विशेष को दे, जाति-विशेष और धर्म-विशेष को या अन्य किसी को? उसके चयन का आधार क्या हो? उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा प्रमुख है या नेताओं द्वारा बनाया गया वह नया 'डिस्कोर्स', जिसमें वह फंस जाता है. 'वंदे मातरम्' और 'भारत माता की जय' जैसे नारे हमारे जीवन के वास्तविक प्रश्नों से जुड़े नहीं हैं. राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में इसका महत्व था. ये नारे सत्ता-प्राप्ति के लिए नहीं हैं. चुनाव में धर्म, संप्रदाय और राष्ट्रवाद का मुद्दा असली मुद्दा नहीं है. असली मुद्दा है हर हाथ को रोजगार, हर खेत को पानी, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य-सुविधा, सबकी सुरक्षा. इसे नजरअंदाज कर देश की सुरक्षा की बात नहीं की जा सकती. चुनाव का संबंध कर्म की राजनीति से है, न कि धर्म की राजनीति से. 'हिंदुत्व' से बड़ा प्रश्न 'बंधुत्व' का है. मतदाताओं को धर्म, संप्रदाय और जाति में विभाजित कर असली मुद्दे दफना दिये जाते हैं.

बार-बार मतदाताओं का विश्वास घटता गया है. मात्र भाषण से किसी का पेट नहीं भरता. प्रचार-प्रसार हकीकत और वास्तविकता पर कुछ समय के लिए परदा डाल सकता है. मतदाताओं के लिए सर्वाधिक आवश्यक है विवेक-शक्ति और विवेक-चेतना, जो सही-गलत का चयन करती है. जाति-चेतना, धर्म-चेतना हमें खंडित करती है. हिंदुस्तान की संस्कृति विभाजनकारी, विभेदकारी और विभक्तिवादी नहीं है. सत्तर वर्ष के आजाद भारत में पीने का पानी, अच्छे कपड़े, भोजन, घर, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और निर्भीक वातावरण क्यों नहीं हैं? ये सब चुनाव के जरूरी मुद्दे हैं. चुनाव का जरूरी मुद्दा आतंकवाद और राष्ट्रवाद नहीं है. राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र के लोगों की चिंता और उनकी हिफाजत है.

आपके पत्र

आतंक पर चोट

एक लंबे अंतराल के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अंततः सुरक्षा परिषद से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में कामयाबी पा ही लिया. यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत हैं, क्योंकि दिसंबर 1999 में भारत सरकार द्वारा अपहृत विमान के बदले रिहा होने के बाद से ही यह आतंकी अपने संगठन जैश-ए-मोहम्मद के माध्यम से कश्मीर समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा और पिछले दिनों सेना पर हुए पुलवामा हमले की भी जिम्मेदारी ली. इस लिहाज से अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराना आतंक के विरुद्ध हमारी लड़ाई का एक अहम कदम है. इस कामयाबी में चीन के अपने अड़ियल रवैये से इतर सहयोग की भी तारीफ करनी होगी, जो अक्सर दुर्भावना से ग्रसित हो इस प्रस्ताव पर अपना वीटो पावर लगा दिया करता था. अब अगर चीन का यह समर्थन दोनों देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक या सुरक्षा के मधुर संबंधों में तासीर का काम करें तो शायद कोई आश्चर्य न हो.

मनोज पांडेय बाबा, चंदनक्यारी, बोकारो

बलात्कार की बढ़ती घटनाएं

पिछले कुछ दिनों में हुए बलात्कार की घटनाओं ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है. राजधानी रांची में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना ने सचमुच प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है. आये दिन हो रहीं ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? गुड़गांव में एक बुजुर्ग महिला द्वारा छोटे कपड़े पहनने पर की गयी टिप्पणी का सभी ने पुरजोर विरोध किया. यह सच है कि ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ छोटे कपड़े ही जिम्मेदार नहीं होते. अगर होते, तो पांच वर्ष की बच्ची हो या 70 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म न हुआ होता. इसके लिए जिम्मेदार हमारी सोच, हमारी मानसिकता है. हम आधुनिकता के इस दौड़ में पाश्चात्य संस्कृति को तो अपनाने लगे पर उसके अनुरूप अपने सोच को विकसित नहीं कर पाये. यदि पुरुष जिस प्रकार अपनी मां, बीवी व बहन का सम्मान करता है, उसी तरह सभी महिलाओं का सम्मान करे तो समस्या ही खत्म हो जायेगी.

कन्हाई लाल, रांची

जल संरक्षण बेहद जरूरी

वर्तमान समय में विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी जल संकट की समस्या ज्वलंत है. जिस भारत में 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से घिरा हो, वहां आज स्वच्छ जल उपलब्ध न हो पाना, एक विकट समस्या है. तीव्र शहरीकरण से तालाब और झीलों जैसे परंपरागत जलस्रोत सूख गये हैं. उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में भूजल स्तर में हर साल 20 सेंटीमीटर से अधिक की गिरावट आ रही है. भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2,000 घनमीटर है, लेकिन यदि परिस्थितियां इसी प्रकार रहीं, तो अगले 20-25 वर्षों में जल की यह उपलब्धता घटकर 1500 घनमीटर रह जायेगी. इसका मतलब पीने के पानी से लेकर अन्य दैनिक उपयोग तक के लिए जल की कमी हो जायेगी. बढ़ती आबादी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उपलब्ध संसाधनों के प्रति लापरवाही ने मनुष्य के सामने जल का संकट खड़ा कर दिया है.

अमन सिंह, बरेली, उत्तर प्रदेश

कुछ अलग

इत्ते प्रतिशत, उत्ते प्रतिशत

आलोक पुराणिक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

उस परीक्षा में वह लड़की 99 प्रतिशत नंबर ले आयी, पर वह 100 प्रतिशत खुश न थी. एक प्रतिशत नंबर कम क्यों आये, यह दुख था. जिस तरह से परीक्षाओं में नंबर-वितरण हो रहा है, उसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय गणित परिषद् यह भी फैसला कर सकती है कि अब सौ में से 110 नंबर देना या 150 नंबर देना भी गणितीय तौर पर वैध माना जायेगा. नंबर फट रहे हैं, सौ प्रतिशत के दायरे में ना समा रहे.

इस कदर प्रतिशतबाजी हो रही है कि उस टीवी चैनल पर एंकर कह रहा था कि केजरीवालजी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में 99 परसेंट था. पचास परसेंट हो भी सकता था, 49 परसेंट नहीं भी हो सकता था, कुल मिला कर 99 परसेंट था.

मामला पेचीदा है, पॉलिटिक्स में कुछ भी काम शत-प्रतिशत ना होता. जो नेता अभी राष्ट्रवाद के नाम पर शत-प्रतिशत झूलता दिख रहा है, वह कल ही एकदम घनघोर सेकुलरत्व की ओर कूच कर सकता है, तब भी वह शत-प्रतिशत सेकुलर नहीं होगा. इसलिए नेता का कुछ भी शत-प्रतिशत कभी न होता. शत-प्रतिशत तो सिर्फ नेता की कुर्सी-आकांक्षा होती है, ऐसे-वैसे या चाहे जैसे भी मिल जाये कुर्सी.

शरद पवार क्या शत-प्रतिशत कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ हैं, इस सवाल का जवाब शत-प्रतिशत देना मुश्किल है, शरद पवार लगभग कांग्रेसी हैं, पर अगर यह गुंताड़ा लग गया कि तमाम दलों के समर्थन से उनके खुद के पीएम बनने का स्कोप हो जाये, तो वह कांग्रेस के विरोधी हो सकते हैं. केजरीवाल शत-प्रतिशत कांग्रेस विरोधी थे, फिर शत-प्रतिशत कांग्रेस समर्थक बनने को तैयार हो गये. अब वह लगभग कांग्रेस समर्थक भी हो सकते हैं, मौका और मुकाम देख कर.

आंध्र के चंद्राबाबू नायडू के बारे में कोई भी कभी भी नहीं कह सकता है कि वह शत-प्रतिशत किधर के हैं. आंध्र के नेता जगन रेड्डी के पिता कांग्रेस के बड़े नेता थे, जगन कांग्रेस के विरोधी हैं, पर क्या वह मोदी के साथ हैं? जी, इस सवाल का शत-प्रतिशत पक्का जवाब नहीं दिया जा सकता. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि शत-प्रतिशत तो नेता कुर्सी को लेकर ही होता है कि मिलनी चाहिए.

बहुत पहले महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे मोदी के साथ थे शत-प्रतिशत. अब वह मोदी के खिलाफ हैं शत-प्रतिशत. राज ठाकरे शत-प्रतिशत किसके साथ हैं, यह अभी नहीं पता. किसी भी मसले पर नेता लगभग होने के बिंदु पर हो, तब ही नेता सा दिखता है. किसी भी बिंदु पर एकदम पक्की राय तो वैज्ञानिक होने का भ्रम दे देती है. पक्का हो जाये नेता, तो उसका पतन सुनिश्चित है, लगभग रहे, तो इधर से उधर भाग सकता है. उधर से फिर इधर भाग सकता है. कहीं लग और फिर यहां से भाग, राजनीतिक तौर पर लगभग होने में ही मजे हैं. पक्का नेता वैज्ञानिक के स्तर पर पतित हो जाता है. वैज्ञानिक चेतना वाला बंदा किसी कोने की किसी प्रयोगशाला में तो काम कर सकता है, पर नेतागिरी नहीं कर सकता. लगभग होने में ही नेता का विकास है. विकास ही क्या, नेता का अस्तित्व ही लगभग होने में है.

देश दुनिया से

जापान के नये सम्राट हुए जनता से मुखातिब

बीते शनिवार को जापान की राजधानी टोक्यो में जापान के नये सम्राट नारूहितो और उनकी पत्नी महारानी मसाको ने पहली बार अपने महल की बालकोनी से हाथ हिला कर बाहर बधाई देने के लिए खड़ी जनता की भीड़ का अभिवादन किया. अपने नये सम्राट को देखने के लिए घंटो पहले से ही जनता महल के बाहर इकट्ठा होने लगी थी. ऐसा माना जाता है कि प्रायः ऐसा तभी होता है, जब जापान में नये साल के जश्न का मौका होता है या फिर सम्राट के जन्मदिन का दिव्य अवसर होता है, तब जापानी लोग महल के बाहर खड़े होकर अपने सम्राट को बधाइयां देते हैं. सम्राट नारूहितो ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें. उन्होंने आगे कहा कि मैं भविष्य में अपने देश की तरक्की देखना चाहता हूं और बाकी देशों के साथ मिल कर चलने के साथ ही वैश्विक शांति चाहता हूं. गौरतलब है कि नारूहितो के पहले उनके पिता अकीहितो जापान के सम्राट थे और जापान में परंपरा है कि वहां सम्राट अपने जीवनपर्यंत रहते हैं. लेकिन यह पहली बार है, जब अकीहितो ने 85 साल की उम्र में सम्राट का पद त्याग दिया. इसी के बाद नारूहितो की ताजपोशी तय हुई.

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है